यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत-अमेरिका वार्ता के लिए यह नया प्रारूप स्वागत योग्य कदम है। लेकिन यह स्पष्ट दृष्टि और निर्धारित नेतृत्व के बिना सफल नहीं हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोनों अपने अपने देशों के प्रमुख कलाकारों अर्थात विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ मिलकर नए स्तर पर बातचीत का निर्माण करते हुए दीर्घकालिक व्यापार के विवाद को निपटाने और भारत-अमेरिकी रणनीतिक संबंधों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों में, राजनयिकों का मानना है कि इस तंत्र से दोनों देशों के बीच सामरिक और सुरक्षा संबंधों को नया आयाम मिलेगा, साथ ही सामान्य चुनौतियों जैसे चीन के आक्रमण से इसकी परिधि पर संकट या पश्चिम एशिया में अस्थिरता से ऊर्जा सुरक्षा के लिए उत्पन्न हुई संकट पर भी व्यापार के मुद्दों पर मतभेद के बावजूद सहायता किया जाना चाहिए। मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके समकक्ष रेक्स टिल्लरसन ने इस प्रक्रिया अर्थात 2 + 2 के प्रारूप पर चर्चा की और अपनी सहमति व्यक्त की।

यह 2 + 2 प्रारूप जापान से लिया गया है, जिसका उपयोग जापान अमेरिका, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक बातचीत के लिए उपयोग करता है। वर्ष 2010 से, भारत और जापान ने अपने विदेशी और रक्षा सचिवों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत शुरू की थी, जो वर्ष 2014 में संबंधित मंत्रियों के स्तर तक पहुँच गया था। देखा जाये तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति ट्रम्प ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद अपने समकक्ष जनरल एचआर मैक मैस्टर के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया था। हांलाकि, यहाँ इस बात का थोड़ा संदेह है कि 2 + 2 इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक नया शक्तिशाली तंत्र प्रदान करेगा और दोनों देशों के नौकरशाहों को इस विचार से प्रेरित होने से बचना होगा कि अकेले यह प्रक्रिया ही मुद्दों को हल कर सकती है।

देखा जाये तो वर्तमान में 60 से अधिक भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय संस्थान मौजूद हैं, लेकिन वाशिंगटन डीसी में नई दिल्ली द्वारा इसकी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करने में विफलता के कारण रोष बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं, अर्थात नौकरशाही जड़ता, कानूनी मुद्दे, अमेरिका के इरादों पर संदेह और रणनीतिक संबंध से भारत क्या चाहता है, पर स्पष्टता की कमी। शायद अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक संवाद तंत्र स्वयं बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यापार जैसे मुद्दों के नतीजे से सामरिक संबंधों को नहीं बचाएगा, जब तक कि राजनीतिक नेता अपने उद्देश्यों पर स्पष्ट नहीं होते। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प की चिंताओं को पूरा करने में कुछ दूरी तय की है, जो व्यापार घाटे को कम करने के प्रयास में अमेरिका से शेल आयल आयात करने पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि, एक गंभीर समस्या यह है कि एशिया के लिए व्हाइट हाउस की एक स्पष्ट दृष्टिकोण की कमी और इसमें अमेरिका की भूमिका, भारत-अमेरिकी संबंधों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एशिया में अन्य सहयोगियों के साथ भी इसके संबंध अच्छे हैं। इसलिए इस समस्या को एक तंत्र के द्वारा नहीं, बल्कि इसे एक दृढ़ संकल्पित राजनीतिक नेतृत्व द्वारा ही हल किया जा सकता है।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जून में हुए शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका और भारत दोनों की नीति विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली। यात्रा का एक प्रमुख परिणाम अमेरिका-भारत रक्षा और सुरक्षा संबंधों में सुधार से संबंधित था।

क्या है खास -

1. रक्षा संबंधों की वृद्धि आश्चर्यजनक से कम कुछ नहीं है, लगभग एक दशक के अंतराल में रक्षा व्यापार अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक का था।
2. अमेरिका और भारत कई और संयुक्त अभ्यासों में भाग लेंगे हैं और अमेरिका अब अपने सबसे करीबी सहयोगियों के अनुरूप एक संवेदनशील स्तर पर भारत के साथ संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के साझाकरण को अधिकृत करता है।
3. आतंकवाद सहयोग और खुफिया साझाकरण पर ध्यान देने के साथ-साथ इस बार सुरक्षा साझेदारी को भी मजबूत किया गया है।

संयुक्त घोषणा पत्र-

1. ट्रम्प और मोदी द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य ने उपर्युक्त कथन को रेखांकित किया है और वास्तव में रक्षा सहयोग के लिए इस रणनीतिक तर्क को व्यापक बनाया है।
2. ''सामान्य सिद्धांतों'' जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य की सार्वभौमिकता के संबंध में एक समूह का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र-एशिया सहयोग के लिए अनिवार्यता की पुष्टि 2015 संयुक्त रणनीतिक विजन में की गयी है।
3. इसके अलावा इसमें नेविगेशन की स्वतंत्रता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की भी अंतर्निहित आलोचना की गयी है जो साझा चिंताओं को दर्शाती है कि चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे छोटे देशों की आजादी को सीमित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाएगा और उत्तर कोरिया, जो अपने पड़ोसी को नियंत्रित करने के लिए चीन के समान ही पैंतरें अपना रहा है, पर सशक्त लगाम लगाना शामिल किया गया है।

4. अमेरिका के प्रमुख रक्षा साझेदार (पिछले साल घोषित) के रूप में भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए ट्रम्प ने आगे के सहयोग के लिए कई अवसरों को उजागर कर दिया है।
5. जिसमें समुद्री डोमेन जागरूकता पर गहरा सहयोग और वार्षिक अमेरिका-भारत-जापान MALABAR अभ्यास पर निवेश शामिल है, जिसे ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से ''विशाल हिंद महासागर में किए गए सबसे बड़े समुद्री व्यायाम'' के रूप में वर्णित किया है और जिसमें एंटी-पनडुब्बी युद्ध पर अधिक ध्यान दिया गया है।
6. इस शिखर सम्मेलन में यह घोषणा की गयी थी कि अमेरिका ने 22 सागर गार्जियन मानव रहित एरियल सिस्टम की बहु-अरब डॉलर की बिक्री की पेशकश की थी, जिसे मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के तहत ''अस्वीकृति की अनुमानितता'' पर काबू पाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता थी।
7. उनको खरीदना भारत के समुद्री निगरानी के लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन अन्य लंबी दूरी की अमेरिका की बिक्री के लिए दरवाजा भी खोल सकता है।

तीन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता

1. सबसे पहले यह है कि हमे रक्षा बिक्री की स्थिर गति देखने को मिलेगी। भारत लंबे समय से रक्षात्मक आधुनिकीकरण के बीच फंसा हुआ है, लेकिन नई दिल्ली की समझदारी ने अमेरिका-भारत रक्षा व्यापार के बढ़ते मांग को समझते हुए इस द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया।
2. अमेरिका द्वारा कुछ संवेदनशील तकनीकों का प्रकाशन ऐतिहासिक रूप से सभी चार प्रमुख गैर-प्रसार शासनों में देश की सदस्यता पर किया गया है। भारत एमटीसीआर का सदस्य है, और अब वसीनर व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है, साथ ही वाशिंगटन चीन के समक्ष नई दिल्ली को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता के लिए तरफदारी कर रहा है।
3. तीसरा और अंतिम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से संबंधित है। मोदी और ट्रम्प दोनों ने सीमा सुरक्षा को बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह स्पष्ट है कि भारत अमेरिका से 11 सितंबर, 2001 के बाद से अमेरिका द्वारा अपनी घरेलू सुरक्षा को बढ़ाए जाने के तरीके से एक बहुत कुछ सीख सकता है।
4. सीमा सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अमेरिकी तकनीकी सहायता को बढ़ाने के लिए खुफिया आदान-प्रदान करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जारी युद्ध को जीता जा सकता है।

इससे संबंधित तथ्य

- ट्रंप के अनुसार भारत 'ट्रेड बैरियर' को और शिथिल करे, ताकि अमेरिका अधिक निर्यात कर सके और अमेरिकी जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। तब बात समझ में आ गई कि यह राष्ट्रपति से अधिक एक कुशल व्यापारी है।
- यह देखने वाली बात थी कि ट्रंप को 'अमेरिका फर्स्ट' याद रहा, मगर मोदी 'मेक इन इंडिया' का नारा भूल गये। ट्रंप अपने चुनावी वायदे के प्रति गंभीर हैं, यह स्पष्ट दिख रहा था। दो अरब डॉलर की ड्रोन डील, अमेरिकी कंपनी लॉकलीड मार्टिन द्वारा 70 अदद एफ-16 की सप्लाई और उसके रखरखाव व कलपुर्जों के लिए टाटा से समझौते को लेकर अमेरिका का उद्योग जगत खुश है।
- उससे पहले नागरिक विमानों की बड़ी खेप भारत में निर्यात किये जाने को उद्धृत करते हुए ट्रंप ने संदेश दिया कि इससे अमेरिकी नागरिकों को रोजगार के बड़े अवसर मिलने जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना को 200 अत्याधुनिक युद्धक विमानों की आवश्यकता है।
- इसके एक बड़े हिस्से का निर्यात अमेरिका करेगा, इसे ट्रंप की व्यापारिक सफलता के नुक्ते नजर से देखा जाना चाहिए। आगे ट्रंप यह चाह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स, पेटेंट बीज, कृषि उपकरण, नाभिकीय ऊर्जा, इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में जो नियामक बाधाएं हैं, भारत उसे सरल करे और 'फ्री एंड फेयर ट्रेड' का मार्ग प्रशस्त करे।
- ट्रंप ने जीएसटी को जल्द लागू किये जाने को जिस तरह से सराहा, इससे साफ था कि भारत में कर प्रणाली में हो रहे बदलाव पर अमेरिका की गहरी नजर है।
- इस यात्रा से पहले यह आशा थी कि मोदी 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को आगे बढाएंगे। मगर, यह हुआ नहीं। एच1-बी वीजा पर चर्चा की उम्मीद 30 लाख अमेरिकन-इंडियन कर रहे थे।
- उनमें 700 से अधिक सिलिकॉन वैली की भारतीय कंपनियों को भरोसा था कि इसका रास्ता निकलेगा। मगर, इस विषय को सूची से बाहर रखा गया था। उसी तरह 'पेरिस पर्यावरण संधि' जैसे मुद्दे को मोदी ने दूर ही रखा। उलटा, ट्रंप ने कहा कि भारत से उभयपक्षीय व्यापार में घाटा हम उठा रहे हैं, उसे मोदी ठीक करें।
- अमेरिकी गृह मंत्रालय का एक महकमा है, 'ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिजम।' इस विभाग का काम है, दुनिया भर के दहशतगर्द संगठनों और उनके नेताओं को 'ग्लोबल टेररिस्ट' घोषित करना और जब वे दुरुस्त हो जाएं तो उनके नाम को सूची से बाहर कर देना। आतंकी सरगना हाफिज सईद अब इस सूची में 61वें नंबर पर हैं।

संभावित प्रश्न

"भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय सामरिक संबंध उनके 'साझा मूल्यों एवं हितों' तथा 'वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता' पर आधारित हैं।'' इस कथन का विश्लेषण कीजिए। **(200 शब्द)**